

लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा करने का विचार रखती हैं;

(ख) यदि हां, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त पैकेज की घोषणा कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस पैकेज के फलस्वरूप संचार सेवा की स्थिति में किस हद तक सुधार होने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क)

से (घ) सरकार द्वारा नई दूरसंचार नीति पर सिफारिशें देने के लिए एक दूरसंचार दल का गठन किया गया है। यह दल अन्य बातों के साथ-साथ संचार के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर द्वारा अदा की जा सकने वाली भूमिका पर विचार कर रहा है। मार्च, 1999 के अंत तक इस दल की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के संभावना हैं। दल की सिफारिशें मिल जाने के बाद सरकार अपना दृष्टिकोण तय करेगी।

Development of Tourism in Tamil Nadu

*2. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the number of proposals received from the State Government of Tamil Nadu for development of tourism in the State;

(b) the number of proposals cleared till 31st December, 1998; and the details thereof; and

(c) the number of proposals pending and the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF TOURISM (SHRI ANANTH KUMAR): (a) to (c) Ministry of Tourism in consultation with State Government have prioritised 20 projects for Central Financial Assistance during the year 1998-99 for Rs. 435.00 lakhs. Proposals for 13 projects were received from the State Government. However, on scrutiny of the proposals it was found that the proposals were incomplete as per the Guidelines laid down by the Ministry of Tourism. Therefore, no projects were sanctioned till 31.12.1998. Subsequently however, seven projects amounting to Rs. 87.81 lakhs were sanctioned.

बाली बीमा कारोबार

*3. श्री ईश दत्त यादव :

चौधरी हरमोहन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में चालू जाली बीमा कारोबार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जाली बीमा कारोबार जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों, एजेंटों और निगम के कार्यालयों की मिलिभगत से चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप जीपन बीमा निगम को भारी घाटा हो रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में जीवन बीमा निगम के कार्यकरण को सरल एवं कारगर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रैस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादाम्बूर एम0आर0 जनार्दनन) : (क) और (ख) पिछले कई वर्षों में सरकार के नोटिस में जीवन बीमा निगम में जाली बीमा कारोबार के मामले आये हैं।

(ग) और (घ) हां। पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है;

वर्ष	संख्या
1995-96	8
1996-97	3
1997-98	शून्य
1998-99	शून्य

(ड.) सरकार ने इन अनाचारों की जांच करने हेतु केन्द्र सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य सचिव श्री ए0वी0 गणेशन की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की थी। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है जिससे अनाचारों को नियंत्रित करने में सहायता मिली है।

National Judicial Commission

*4. SHRI PRAFULL GORADIA:

SHRI SOUPETA RAMACHANDRA REDDY:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that eminent jurists, former police officials and